Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Saboo, Shri Shri Gopal
Saha, Dr. S. K.
Saigal, Shri A. S.
Saleem, Shri M. Yunus
Sanghi, Shri N. K.
Sankata Prasad, Dr.
Savitri Shyam, Shrimati
Sayeed, Shri P. M.
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri
Shashi Bhushan, Shri
Shastri, Shri Biswanarayan
Shastri, Shri Ramanand
Sheo Narain, Shri
Sher Singh, Shri
Shinde, Shri Annasahib
Shukla, Shri S. N.
Siddheshwar Prasad, Shri
Singh, Shri D, N.
Sinha, Shri R. K.
Snatak, Shri Nar Deo
Sonar, Dr. A. G.
Sonavane, Shri
Sudarsanam, Shri M.
Supakar, Shri Sradhakar
Swaran Singh, Shri
Tarodekar, Shri V. B.
Tiwary, Shri D. N.
Tiwary, Shri K. N.
Uikey, Shri M. G.
Ulaka, Shri Ramachandra
Venkatasubbaiah, Shri P.
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra

MR. SPEAKER : The result* of the division is : AYES : 15 ; Noes 164 ; Abstentions 29.

The motion was negatived.

MR. SPEAKER : I shall now put substitute motion No. 12 by Shri Kabir to the vote of the House.

Substitute motion No. 12 was put and negatived.

MR. SPEAKER : I shall now put substitute motion No. 17 by Shri Tenneti Viswanatham to the vote of the House.

Substitute motion No. 17 was put and negatived.

SHRI CHANDRIKA PRASAD : I am not pressing my substitute motions Nos. 15 and 16. I seek leave of the House to withdraw them.

Substitute motions Nos. 15 and 16 were, by leave, withdrawn.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal) : The doors are continuously closed and members are held up outside.

MR. SPEAKER : I know that was agreed. 15 or 18 makes no difference.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : People should think that there is sec. 144 inside.

MR. SPEAKER : I shall now put substitute motion No. 7 by Shri Shri Chand Goyal to vote.

Substitute motion No. 7 was put and negatived.

MR. SPEAKER : All the substitute motions are now disposed of. We now proceed to the next item on the agenda.

SHRI RANGA : Therefore, the plan has been dismissed.

16.55 hrs.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL—*contd.*

MR. SPEAKER : The House will now take up further consideration of the Companies (Amendment) Bill. Shri Kanwar Lal Gupta was on his legs...*(Interruptions.)*

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : So, the Plan has not been approved by the House.

MR. SPEAKER - It is only motion for consideration of the Plan.

AN HON. MEMBER : What is the time for general discussion ?

*The following Members also recorded their votes : AYES : Shri Kedar Paswan. NOES : Sarvashri C. D. Gautam and S. M. Solanki.

MR. SPEAKER : Still three and a half hours are left. I think we can take another one and half hours for general discussion.

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली-सदर): अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैंने मंत्री महोदय को इस बात पर बधाई दी थी कि वह सदन के सामने यह विधेयक लाये हैं। मैंने यह भी कहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निर्लिंगप्पा ने इसका विरोध किया है कि इस प्रकार की पाबन्दी कम्पनियों पर लगाई जाय। मैंने यह भी कहा था कि कांग्रेस नेता श्री पाटिल और श्री अतुल्य घोष ने भी इसका विरोध किया है। लेकिन उसके बाद भी मंत्री महोदय ने इतनी हिम्मत दिखाई है, इसलिये मैंने उनको मुबारकबाद दी थी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे पाटिल साहब के जीतने की खबरें आ रही हैं, अभी तक 20 हजार वोट से जीत रहे हैं, वैसे वैसे मंत्री महोदय के पांव डगमगा रहे हैं। मैंने सुना है कि अब सरकार यह विधेयक सिलैक्ट कमेटी को भिजवाना चाहती है और इस तरह से इसमें देर करना चाहती है। हमारी पार्टी इसका पूरी तरह से विरोध करेगी। हम चाहते हैं कि पूरी तरह से पाबन्दी लगाई जाय और इसमें किसी प्रकार का ज्यादा समय खराब न किया जाय।

किस प्रकार से इसके जरिये पोलिटिक्स को करप्ट किया जा रहा है, इसके बताने की जरूरत नहीं है। कभी तो हम साहू-जैन पर एन्कवावरी कराते हैं और कभी बिरला पर एन्क्वायरी कराते हैं और यह एलीगेशन लगाया जाता है कि उन्होंने करप्ट मीन्ज से बहुत सारा धन इकट्ठा किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनके पक्ष या विपक्ष में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही है कि ये बड़े-बड़े इंडस्ट्रीयल हाउसेज इस पार्टी-इन-पावर को करोड़ों रुपया चन्दा दे रहे हैं और जिसके कारण से उन्हें लाइसेंस मिलते हैं, तरह तरह के फेवर मिलते है। मैं चाहता हूँ कि सरकार एक कमीशन बैठाये जो केवल एक हाउस के लिये नहीं—एक बिजनेस हाउस के खिलाफ एन्क्वायरी कराकर तो एक तरह से पोलिटीकल ब्लैक-मेलिंग हो रही है—अगर यह सरकार सिन्सीयर है तो इस बात की एन्क्वायरी कराये कि कन्सेन्ट्रेशन आफ वैल्थ कैसे हो गया ? क्या इसमें मंत्री शामिल नहीं हैं, क्या वह पार्टी शामिल नहीं है जिनको करोड़ों रुपया चन्दा दिया जाता है, क्या बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं ? जब उनको चन्दा दिया जाता है तो वे बड़े देशभक्त हैं और जब चन्दा नहीं दिया जाता तो उनकी देशभक्ति खत्म हो जाती है—इस प्रकार के दो स्टैंडर्ड की बात करना, अध्यक्ष महोदय, ठीक नही होगा।

अध्यक्ष महोदय, मोनोपली कमीशन रिपोर्ट में भी, संथानम कमेटी ने भी, मजूमदार कमेटी ने भी जो कम्पनी-ला एडमिनिस्ट्रेशन के लिये बनाई गई थी और ए०आर०सी० ने भी इस बात को रिकमेंड किया है कि इस प्रकार के डोनेशन्ज पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सुन्दर चेहरा और

16.59 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

वह भी किसी युवक का और उसमें भी अगर महिला हो तो बड़ा आनन्द दायक होता है, अगर वह मुस्कराये तो हर एक सुन्दर चेहरे की मुस्कराहट को दूसरा व्यक्ति पसन्द करता है। और चाहता है कि ऐसा मौका उसको देखने को मिले। लेकिन व्यापारी को किसी सुन्दर चेहरे की मुस्कराहट नहीं चाहिये, वह तो मंत्री की मुस्कराहट चाहता है चाहे उसका चेहरा कितना ही भद्दा क्यों न हो। क्योंकि वह कमर्शियल मुस्कराहट चाहता है उसको किसी युवक या युवती की मुस्कराहट की दरकार नहीं है। उसके सामने अगर मंत्री हंस देगा तो उसको लाइसेंस या कोटा या परमिट आसानी से मिल जायगा।

कैलकटा हाई कोर्ट का एक जजमेंट मैं कोट करना चाहता हूँ। सवाल पूछते हैं और उसका जवाब भी जजेज ने ही दिया है। यह एक

कम्पनी का केस था, हाई कोर्ट के जजेज ने क्या कहा है :

"What is the motive behind company donation" ? The answer was :

"Whatever be the ethics of such conduct, even a smile of a Minister or a nod or a frown of an executive authority amenable to a Minister, either of the State or of the Centre, amounts to a very great help for businessmen or industrialists in getting priorities, in resolving labour disputes, in getting licences and so on. This contribution was inspired by nothing, less than motives of commercial expendiency and for promotion of the company's business interests."

यह जो पैसा दिया जाता है यह बिजनेस इंटरेस्ट के लिए दिया जाता है। किसी पार्टी का कोई प्रोग्राम है इसलिये नहीं दिया जाता है। मुझे हंसी भी आई जो फैडरेशन आफ चैम्बर्स ऐण्ड कामर्स के अध्यक्ष, जिनका जिक्र अभी पहले आया था, श्री गूजरमज मोदी, जिन को सरकार ने पद्म विभूषण भी दिया है, अभी हाल में प्रधान मंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि आप यह बिल वापस ले लें। हम तो सरकार को पैसा देना चाहते हैं। कम्पनी पर किसी तरह की पाबन्दी नहीं होनी चाहिये। बहुत प्यार है आपसे उनको। प्यार क्यों है ? यह जो बड़े बड़े सरमायेदार हैं क्यों प्यार करना चाहते हैं, क्यों वह आपकी मुस्कराहट चाहते हैं ? मुस्कराहट आते ही एक स्कूटर के टायर का लाइसेंस मिल जाता है, कोटा, परमिट मिल जाता है। यह एक अजीब बात है, उन्होंने जो प्राइम मिनस्टर को मेमोरेन्डम दिया उसमें कहा कि हर एक आदमी को अपनी पोलिटिक्स को इनफ्लूंस करने का हक है, किसी भी पोलिटिकल पार्टी को अपनाने का हक हूँ। मैं मानता हूँ कि हर एक आदमी को यह राइट है कि राजनीति को इनफ्लूएंस करे। लेकिन अपने पैस से करे तो ठीक है। लेकिन शेयर होल्डरों के पैसे से आप अपना बिजनेस चलायें इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकसा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि 117 कम्पनियों में जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपये है पब्लिक सेक्टर के लगभग 25 परसेंट शेयर हैं और जो डोनेशन 117 कम्पनियां देती हैं इसका मतलब यह है कि उसका चौथाई रुपया कम से कम जनता का होता है। क्योंकि सरकारी रुपया इसमें लगा रहता है। इसी तरह से जो और बड़ी कम्पनियां हैं, जो शेयर होल्डर हैं पैसा उनके पास से जाता है और बड़े बड़े लोग उसका लाभ उठाते हैं यह एक इसकी विडम्बना है। अगर कोई सरमायेदार या इंडस्ट्रियलिस्ट यह चाहे कि वह डोनेशन दे तो अपनी जेब से दे हमें कोई एतराज नहीं, वह पौलिटीकल को इनफ्लूएंस करें, हमें एतराज नहीं है। लेकिन दूसरे के पैसे से अपना उल्लू सीधा करना यह ठीक नहीं है।

आपको याद होगा यहां एक बहुत बड़े नेता ने यह बात कही थी कि अगर मेरे पास 50 लाख रुपया होतो मैं मिनिस्टर बन सकता हूँ एक स्टेट के अन्दर। अगर एक करोड़ रुपया हो तो चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ और अगर दो करोड़ रुपया हो तो देश का प्रधान मंत्री बन सकता हूँ। यह बात कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने कही। मेम्बर बिकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में उनीकी लग्जूरियस लाइफ होती है। वह किसी भी पार्टी के क्यों न हों। हम यहां पर आये हैं लोगों की आवाज उठाने के लिये। तो मैं कहना चाहूंगा कि यह जो कलंक हमारे ऊपर है यह हमेशा के लिये खत्म होना चाहिये, देश में अगर डेमोक्रेसी रहनी है तो इसको खत्म होना चाहिये। जब तक यह चीज खत्म नहीं होगी तब तक देश का कल्याण नहीं होगा।

लेकिन यह जो बिल आपने रखा इससे कोई पूरा सौल्यूशन हो जायेगा ऐसा मैं नहीं मानता। यह इनकमप्लीट है। आज आपने कम्पनी पर पाबन्दी लगायी, लेकिन रजिस्टर्ड फर्म पर कोई पाबन्दी नहीं है। कोई भी सरमायेदार पांच, छः पार्टनर बना कर एक फर्म बना लेंगे और फर्म से डोनेशन देंगे। तो एक दूसरा रास्ता निकल जायगा। यह जो ब्लैक मनी है इस तरह से चलेगा। यह पूरा उसका हल नहीं

[श्री कवर लाल गुप्ता]

है । आपको मालूम है कि यह एस्टीमेट किया जाता है कि पिछले चुनाव में करीब 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ कांग्रेस पार्टी का । और केवल तीन करोड़ रुपये का हिसाब हैं कि कहां से आया । बाकी सात करोड़ रुपया कहां से लिया ? क्या यह काला धन नही था ? वह काला धन है । इसलिये इसका सौल्यूशन केवल कानून से नही होगा । मेरी एक मांग तो यह है कि कम्पनी के साथ साथ यह रजिस्टर्ड फर्म पर भी लगना चाहिये । वैसे मुझे तो यह खयाल है कि कहीं यह अनकांस्टीट्यूशनल न हो जाय । क्योंकि केवल कम्पनीं पर पाबन्दी लगाना शायद कांस्टीट्यूशन के खिलाफ होगा । कानून से इसका हल होने वाला नहीं है । नौर्म, स्टैन्डर्ड कोई बनाना चाहिये, आदर्श बनाना चाहिये हर एक पार्टी को कि जो भी मंत्री होगा वह डोनेशन नहीं लेगा, वह किसी चीज के लिये नही लेगा । मैं मांग करूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस चीज की पहल करे । जनसंघ ने यह तय हैं कि हमारा कोई मंत्री किसी प्रकार का डोनेशन किसी चीज के लिये नहीं लेगा, न मांगेगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह बात 16 आना सही है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिये ठेकेदारों से पैसा इकट्ठा किया गया, पईज अकाउंट चैक लिये गये आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नाम । मैं चाहता हूँ कि इसकी इनक्वायरी आप करायें । यह परम्परा देश के लिये घातक है । हो सकता है कि इससे टेम्पोरेरी लाभ हो लेकिन आखिर में यह जड़े काट देगी । डेमोक्रेसी में जिस पार्टी का केस कमजोर हो जाता है, जनता से पार्टी हट जाती है वह बड़े बड़े लोगों की तरफ देखती है । वह ताकत के बल पर राज्य करना चाहती है । लेकिन बहुत दिन तक राज्य नहीं कर सकती ।

गांधी जी ने कहा था कि हम बड़े बड़े पैसे वालों के पास न जायें बल्कि छोटे छोटे लोगों से पैसा लेकर के काम करें । यह तरीका होना चाहिये । मैं मांग करूंगा कि अगर सही माने में इस बिल की स्पिरिट को कांग्रेस मानती है और उस पर अमल करना चाहती है तो ऐसी आचार संहिता बनानी चाहिये ।

अभी गालिब सैंटनरी हुई जिसके मंत्री महोदय अध्यक्ष हैं । बहुत अच्छा काम है । लेकिन क्या जो डोनेशन्स उसमें दिये गये केवल गालिब से मोहब्बत होने की वजह से दिये गये ? नहीं । लाखों रुपया इकट्ठा हुआ । मैं चाहूँगा कि वह लिस्ट मंत्री जी सदन के सामने रखें कि कहां कहां से कितना रुपया आया ताकि लोगों को मालूम हो सके ति इन बड़े बड़े लोगों ने हजारों, लाखों रुपया उसमें दिया है वह क्यों दिया है ।

एक बात और है, मैंने कहा कि इनकम्प्लीट सैल्यूशन है एक बड़े महत्व का सवाल यह आता है कि अगर आप लोगों ने कम्पनियों से डोनेशन लेना बन्द कर दिया, इलेक्शन तो बहुत कास्टली दिन पर दिन होता जाता है, और कुछ पार्टियां उपाध्यक्ष जी ऐसी हैं जो बाहर से पैसे लेती हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन जो पार्टियां हिन्दुस्तान की हैं उनको इस बिल से तकलीफ जरूर होगी तो उसका सरकार क्या इलाज करना चाहती है ? जो बाहर से पैसा लेते हैं और उनकी मोडस औपरेंडी आपको मालूम है क्योंकि आप अच्छे तरीके से उन चीजों के जानते हैं । उनका मोडस ओपरेंडी क्या है इसका एक उदाहरण मैं आपको बतलाना चाहता हूं । कुछ कमिशन एजेंट मैं ने उस दिन मंत्री महोदय को कहा था कि रशिया और इस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को सप्लाई करने के लिए यहां पर कुछ एजेन्ट्स बनाये हुए थे, मंत्री महोदय ने कहा कि वह एजेन्ट नहीं हैं । मैंने मंत्री महोदय को, फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने कहा कि एजेन्ट हैं, जो एजेन्ट एस०टी०सी० के जरिये रशिया या दूसरे यूरोपियन देशों को माल सप्लाई किया करते हैं । मैंने एक का नाम लेते हुए पूछा कि क्या यह सही है कि उस एजेन्ट की तलाशी ली गई ? उससे डुपलीकेट एकाउंट बुक्स मिली । एकाउंट बुक्स में लाखों रुपया काले धन का था और जब इनकम टैक्स डिपार्ट-

मेंट ने उसकी इनक्वायरी की तो यह मालूम हुआ कि रूस से उस फर्म को 5 लाख रुपया मिला है। रूस से मिला हुआ रुपया उनकी किताबों में दर्ज था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट वालों ने पूछा कि यह 5 लाख रुपया रूस ने क्यों दिया तो उसने कहा कि डिवैल्यूशन हुआ है उसका मुआविजा हमें मिला है। लेकिन डीवैल्युएशन 6 महीने बाद हुआ और मुआवजा 6 महीने पहले मिल गया। यह स्वयं फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी चिट्ठी में मुझे लिखा है। मैंने कहा है कि उसकी इनक्वायरी होनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि मंत्री महोदय उसकी इनक्वायरी करा रहे हैं या नहीं ?

इस तरीके ने वह जो 5 लाख रुपया व्यापारी के पास आया उसमें से कुछ तो उधर जायगा, आपको नहीं शामिल करता हूँ, लेकिन वह हैं आपके पीछे बैठने वाले बहुत से लोग, उनकी तरफ जायगा और कुछ वह व्यापारी खायेगा। इसलिए इसका भी कुछ इलाज होना चाहिए क्योंकि जहां हम चाहते हैं कि देश के पूंजीपति हमारे राजनीतिज्ञों पर प्रभाव न डालें वहां अगर विदेशी डालें तो वह और भी खराब बात है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के मामलों में उनका हस्तक्षेप हो। मुझे इस बात का दुःख है कि आज गृह मंत्री जी कहते हैं कि कोई कानून हीं नहीं है कि रूस से कोई पैसा ले लें, फ्रांस से कोई पैसा ले लें तो उनको कैसे रोका जाय ? मैं सरकार से मांग करूंगा कि हम रूस और अमरीका को तो नहीं रोक सकते हैं लेकिन क्या हम अपने देश के लोगों को भी नहीं रोक सकते हैं जिनके बारे में हमें मालूम है कि वह अमरीका से पैसा लेते हैं या वह रूस से पैसा लेते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं का भी पैसा हो, रूस, अमरीका या इंग्लैंड का हो या और कहीं का हो, वह उतना ही खराब है और हम लोगों को ऐसा कानून पास करना चाहिये जिससे हिन्दुस्तान का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो वह अगर उनसे पैसा लेता है तो उसे इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिले।

जहां तक मैनेजिंग एजेंसी का सवाल है मैं दो शब्द कह कर समाप्त करूंगा। मैनेजिंग एजेंसी का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता होने के लिए कभी उसका लाभ रहा है लेकिन अब इस मैनेजिंग एजेंसी का रिवाज और सिस्टम खत्म हो रहा है और मैं समझता हूं कि अब यह खत्म हो जायगा। लेकिन यह बात भी सही है कि कुछ इंडस्ट्रीज में मैनेजिंग एजेंसी कुछ लाभप्रद भी सिद्ध हुई हैं। इसके बारे में भी मंत्री महोदय देखें कि जिन जिन इंडस्ट्रीज में मैनेजिंग एजेंसी की जरूरत है उसके बारे में वह विचार करें लेकिन मैं बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का पूरा विरोध करता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का जो मंत्री महोदय लाये हैं समर्थन करता हूँ और डोनरशिप के बारे में मंत्री महोदय ने जिस मजबूती का परिचय दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

श्री शशि भूषण (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय तथा उन अधिकारियों को जो यह बिल लाये हैं उन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास कर जो कम्पनीज व्यापारिक संस्थान हैं जो राजनीतिक संस्थाओं को चंदा, आर्थिक सहायता देती रही है उस पर प्रतिबन्ध लगाने की बात का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। इसी प्रकार इस बिल का जो दूसरा पहलू है जिसमें मैनेजिंग एजेंसी का मुकर्रर करना है उस पर भी प्रतिबन्ध है और मानता हूँ कि वह भी एक बहुत आवश्यक कदम है।

आज के समय में जब कभी भी इस प्रकार के प्रगतिशील बिल हमारे सदन में आते हैं तो हमारी आशाएं बनती हैं, एक नई दिशा मिलती है, एक नई रोशनी मिलती है। जब भी कभी बाहर से कहीं भी ऐसा परिवर्तन होता है लोगों ने उसका पहले पहल बहुत विरोध किया लेकिन जब उन्होंने यह समझा कि इन कम्पनियों के चन्दे द्वारा लोगों को सोने की बेड़ियाँ और हथकड़ियां पहनाने में सहायता मिलती है तो उन्होंने भी इस बिल को यां हलाने में मदद की। आप जानते है कि इतिहास में 5000 साल से शोषण के खिलाफ एक संघर्ष चलता आ रहा

[श्री शषि भूषण]

है। क्या कभी कोई सोचता था कि किसी जमाने में सामन्तशाही खत्म होगी? क्या पूर्वज सोचते थे कि पोप और ब्राह्मणों का पाखंड भी छूटेगा? लेकिन इतिहास साक्षी है कि लोग उसके खिलाफ लड़े और उन्होंने सामन्तशाही को समाप्त करने में सफलता पाई। इस सामन्तशाही को समाप्त करने के लिए फ्रांस की महान क्रान्ति के जमाने में तीन नारे लगाये गये थे, स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व। हमने देखा कि लिंकन ने स्वाधीनता के लिए प्रेरणा दी, लेनिन ने समानता के लिए प्रेरणा दी और गांधी ने भ्रातृत्व के लिए प्रेरणा दी लेकिन उनका काम अभी अधूरा है। आर्थिक शोषण जोकि सामाजिक शोषण की जड़ होती है वह अभी समाप्त नहीं हुआ है और उसी की वजह से आज हमारे देश में सामाजिक विषमता व आर्थिक विषमता मौजूद है। इधर, उधर का शोषण, तरह तरह के लोगों ने ऐसे इतिहास में रास्ते अपनाये कि किसी तरह भी जनता का जो श्रम है जो उसकी मेहनत है उसको कुछ लोगों के हाथ में रक्खा जाय और उस अधिकार को रखने के लिए बंदूक से सहायता ली गई, धर्म-ग्रंथों से सहायता ली गई और आजकल भी उस शोषण को बरकरार रखने के लिए पिछले 20 साल में इन कम्पनियों ने बहुत मदद दी है जिससे कि जनता की शक्तियां आगे बढ़ न पायें। चंदा देकर आर्थिक सहायता देकर प्रजातंत्र को गंदा करने में उन्होंने बहुत हाथ बंटाया। आज उसका मुकाबला करने के लिये हमारे उद्योग मंत्री जी जो यह बिल लाये हैं उसको मुबारकबाद सारे देश के वह लोग देंगे जोकि जनता की ताकतों के लिए जनता के शोषण के खिलाफ एक नई आवाज बुलन्द कर रहे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त ने अभी कुछ चीजें रक्खीं। उन्होंने बतलाया कि 10 करोड़ रुपया कांग्रेस ने पिछले एलैक्शन में इकट्ठा किया लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी वह फीगर्स कहां तक सही है? इसी प्रकार लोग यह कहते हैं कि नई दिल्ली की एक सीट के लिये 10 लाख रुपया खर्च किया गया। मेरा कहना है कि इन सब बातों में कुछ रक्खा नहीं है। लेकिन में इस बात को मानता हूँ कि अभी भी बहुत सारे रास्ते शोषण के इस देश में मौजूद हैं जिनके जरिये अभी भी निहित स्वार्थों द्वारा राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने की गुंजाइश मौजूद है।

खास तौर से जैसे मफतलाल ग्रुप है उन्होंने 100 ट्रस्ट बनाये हुए हैं। उन ट्रस्ट्स में उनकी फैमिली के कुछ लोग शामिल हैं। ऐसा वह इंकम टैक्स बचाने के लिए करते हैं। उसमें उनको गुंजाइश है कि इधर, उधर वह रुपया कर सकें। जो यह शेयर्स का सट्टा होता है जनता की सम्पत्ति से जो कम्पनियां बनती हैं वह थोड़ा सा हिस्सा राजनैतिक अधिकार के लिए दे देती थीं लेकिन शोषण करती थीं। उनसे उनको लाभ नहीं होता था जो पहले शेयर्श खरीदते थे। शेयर्स का सट्टा बन्द होना चाहिए तब कहीं जाकर इस बिल का लाभ होगा। अब होता यह है कि बड़े सरमायेदार किसी भी छोटी कम्पनीज को खरीद लेते हैं उसके बाद फ्लोटिंग शेयर्श की तरह यह कम्पनियां चलती हैं। सन् 52 में बिड़लाज ग्वालियर कम्पनी लिमिटेड के अन्दर 300 फर्म्स थीं। सन् 52 में जब रैवेन्यु आफिसर ने वहाँ का एसैस किया तो उसके बाद सब कम्पनी फर्म्स गायब हो गई फिर नई कम्पनियां बनीं और फिर पुरानी कम्पनियां आ गई। इन सब बातों को रोकने में यह बिल मदद करेगा और कोई यह नहीं कह सकेगा कि इसमें राजनैतिक संस्थाओं का हाथ है और उनके द्वारा इन कम्पनियों को मदद दी जा रही है।

पिछल दिनों कांग्रेस के चुनाव के लिए जो डोनेशन्ज लिये गये, उनके अलावा हमारे मशहूर शायर गालिब की सेनटेनरी के सिलसिले में जो रुपया इकट्ठा किया गया, उसकी तरफ भी

इशारा किया गया। मुझे पता है कि विवेकानन्द शताब्दी जब मनाई गई, तो उस वक्त भी देश में लाखों रुपया इकट्ठा किया गया। गालिब सेनटेनरी के लिए जो रुपया इकट्ठा किया गया, उसका पूरा हिसाब मौजूद है और उसको एक अच्छे काम में खर्च किया जा रहा है। लेकिन विवेकानन्द शताब्दी के लिए सारे देश में जो रुपया इकठ्ठा किया गया, वह इलैक्शन तक में खर्च हुआ और उस रुपये का कोई हिसाब नहीं है।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैंने तो मंत्रियों द्वारा रुपया इकट्ठा करने के बारे में कहा था।

श्री शशि भूषण : मैंने पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब से कहा है कि यहां के एक्सीक्यूटिव कौंसिलर्ज चन्दा इकट्ठा करने जाते हैं। यहां पर खुले-आम पोस्टर्ज में लिखा जाता है कि आज श्री अटल बिहारी बाजपेयी को एक लाख रुपये की थैली दी जायेगी—उन इलाकों से, जहाँ सिनेमा मंजूर होते हैं, कालोनीज मंजूर होती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह चार्जिज और काउंटर-चार्जिज लगाने से कोई फायदा नहीं है। इन सब बातों को खत्म करना है और उसके लिए कोई रास्ता ढूंढ़ना चाहिए।

आज हमारे देश में तीन करोड़ बेरोजगार मौजूद हैं। आज नहीं तो कल, धीरे-धीरे, इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण ही होगा, क्योंकि यह बेरोजगारी पूंजीवाद की देन है। वैदिककाल में बेरोजगारी नहीं थी। सामन्त युग में बेरोजगारी थी, उस समय दास-प्रथा थी, लेकिन उन लोगों को रात को रोटी मिल जाती थी। इसकी तुलना में पूंजीवादी व्यवस्था में बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ती है कि उसका कोई अन्त नहीं है। आज अगर तीन करोड़ बेरोजगार हैं, तो कल पाँच करोड़ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा हैं, बेरोजगारी पूंजीवाद की देन है। वह अमरीका, इंगलैंड और फ्रांस में भी है। जहां जहाँ इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, वहां बेरोजगारी खत्म हो रही है। हमारे देश में एक तरफ तो अस्सी परसेंट लोगों की आमदनी एक रुपया रोज से भी कम है और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपने संस्थानों में पांच सौ करोड़ रुपया और एक हजार करोड़ रुपये इकट्ठे किये हैं। जब तक इस गरीब देश में इतनी विषमता रहेगी, तब तक वह प्रगति नहीं कर सकेगा।

इस बिल का यह सुपरिणाम होगा कि राजनैतिक पार्टियाँ इन कम्पनियों से चन्दा नहीं लेंगी। एक वक्त आयेगा, जब राजनैतिक कार्यकर्ताओं में हिम्मत आयेगी कि इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर सकें। यह बिल उस दिशा में एक कदम है, इसलिए मैं सरकार और मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूँ।

चुनाव लड़ने वाले लोग आम तौर पर पूछते हैं कि चुनाव के लिये पैसा कहां से आता है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको एक नुस्खा देता हूं। जो भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है, वह अपने एक हजार साथियों को खत लिखे कि मुझे पांच रुपये से लेकर पचास रुपये तक दो, में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति एक हजार आदमियों से पांच रुपये से पचास रुपये के बीच में पैसा नहीं ले सकता है, उसे डेढ़ लाख लोगों के वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह नहीं ले सकता हैं। जनता उस व्यक्ति को जरूर पैसा देगी, जिस के बारे में उसे पता है कि उसे किसी सरमायादार या कम्पनी से पैसा नहीं मिलता है। इस इस देश में करोड़ों रुपये खर्च करके भी लोग हार सकते हैं, क्योंकि इस देश की जनता जाग्रत हो गई है।

जो नुस्खा मैंने बताया है, अगर राजनैतिक कार्यकर्ता उसको अपनायेंगे, तो वे इन कम्पनियों से पीछा छुड़ा सकते हैं और इस देश में एक साफ वातावरण बना सकते हैं, जिसमें सही व्यापार हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके और आर्थिक शोषण खत्म हो सके

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : Sir, The present Bill seeks to ban compa-

[Shri Sezhiyan]

nies' contributions to political parties and also to abolish the system of management of companies by managing agents. There has been an overwhelming public opinion against companies' donations, and the corrupting influence of big business is very apparent. Many judgments given by High Courts have stressed this point very ably. the famous judgment given by Shri Chagla, when he was the Chief Justice of Bombay, has said this very effectively when he said :

> "It is a danger which may grow apace and which may ultimately overwhelm and even throttle democracy in this country."

Another jndgment given by Justice Ramaswami in the Madras High Court in 1960 has also pointed this out as :

> "If this system of companies' contribution to political parties continues, then we would have a government of the people by industrialists and for industrialists."

That is, the corrupting influence of the companies' donations to political parties may bring down the country and throttle the democracy. It will corrupt the very function of democracy.

The Congress Party has been the sole monopolist in the field of amassing companies contribution for a long time. According to the figures supplied to this House on 22nd April, in the years 1966 67, 1967-68 and 1968-69—all combined—, the 75 companies that have been listed in the Monopolies Inquiry Commission's report, have contributed as much as Rs. 1,87,00,000, out of which Rs. 1, 44,00,000, have gone to the coffers of the Congress, i. e., as much as 77 per cent has gone to the Congress. And the big business houses have never lagged behind in supporting the Congress, especially the Birla House which is much in the talk of the Honse. They have contributed from 1963-64 to 1967-68 as much as Rs. 41 lakhs, out of which the Congress along got Rs. 38 lakhs. This is the state of affairs, and in spite of that, if they have come forward, they probably feel that the winds are changing and the contributions may flow to other parties. I do not want to give the impression that in these figures that have been given our Party has been included, because, in these three years, out of these Rs. 1, 87, 00, 000 not a single pie has come to the D. M. K. Party. The Congress has received, the Swatantra Party has received, the Jan Sangh has received ; SSP. PSP and the Communists have also received, but not the D. M. K. Therefore, I am on the safest grounds.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : Your Party is just born.

SHRI SEZHIYAN : It has been there since 1949 on wards. Probably that is not useful ; we have not benefited them and that is why the big business houses are not contributing to us.

There is another point. I am afraid, the present Bill, even in its amended form, will exclude partnerships and trusts. Therefore, I hope, the Minister will bring a suitable amendment to plug that also because various firms are having trusts and through the trusts they can plough in money.

The second thing, as Mr. Kanwar Lal Gupta pointed out, is the black money coming into the picture, Nobody can believe that the entire Congress electioneering was done by the contribution of Rs. 95 lakhs or Rs. 87 lakhs in 1966-67 or 1967-68. It is well known that Congress has been spending crores of rupees. For example, in 1957, they spent as much as Rs. 5 crores. I can quote the statement made by Shri S. K, Patil himself. As quoted by the *Hindu* of 18th August, 1960 it is said :

> "It is reported that Shri S. K. Patil, Union Minister for Food and Agriculture, said here today that it was becoming more and more difficult to collect funds for fighting elections. During the last General Elections......"

That is, the 1957 elections.

> "..., Shri Patil pointed out, the Congress spent obout Rs. 5 crores."

At that time, these inhibitions were not there and much of the money would have and should have come from unaccounted sources which is otherwise could black-market account.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may continue his speech tomorrow. Now we have to take up the half-an-hour discussion.